+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(06 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- **डोनाल्ड ट्रम्प की गाज़ा को अमेरिकी कब्जे में लेने की योजना और इसके निहतार्थ**
- **अमेरिकी सैन्य विमान से 104 निर्वासित भारतीय वापस लाए गए**
- **विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति के दूसरे विकास इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र**

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

डोनाल्ड ट्रम्प की गाज़ा को अमेरिकी कब्जे में लेने की योजना और इसके निहतार्थ:

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 फरवरी को वाशिंगटन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद, एक चौंकाने वाली घोषणा में कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर "कब्जा करेगा" और इस क्षेत्र को "मध्य पूर्व का रिवेरा" बनाने के लिए फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से कहीं और बसाएगा।
- उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस आश्चर्यजनक योजना गाजा से पड़ोसी देशों में फिलिस्तीनियों के स्थाई पुनर्वास के उनके पहले के प्रस्ताव के बाद आई है।
- हालांकि गाजा पर नियंत्रण करने और फिलिस्तीनियों को पुनर्स्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की नई योजना इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति अमेरिका की दशकों पुरानी नीति को ध्वस्त कर देगी और इजरायल और हमास के बीच नाजुक युद्ध विराम को खत्म कर देगी।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने वास्तव में क्या कहा है?

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कब्ज़े में लेगा और इसके साथ काम भी करेगा। अमेरिका इसका मालिक होगा और साइट पर मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने, साइट को समतल करने और नष्ट हो चुकी इमारतों से छुटकारा पाने के लिए जिम्मेदार होगा। एक ऐसा आर्थिक विकास करेगा जो क्षेत्र के लोगों के लिए असीमित संख्या में नौकरियां और आवास प्रदान करे। असली काम करें। ट्रम्प ने पूछे जाने पर कहा कि यह सब हासिल करने के लिए, अगर जरूरी हुआ तो अमेरिकी सेना भी भेजी जाएगी।
- जब उनसे पूछा गया कि नए गाजा में कौन रहेगा, तो ट्रम्प ने कहा, "मैं वहाँ दुनिया के लोगों को, दुनिया भर के प्रतिनिधियों को, फिलिस्तीनियों को भी रहने की कल्पना करता हूँ"।

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी तरह के जबरन विस्थापन को प्रतिबंधित करता है, जो एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप गाजा के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

- बहुत से लोग राष्ट्रपति ट्रंप के रुख को "साम्राज्यवादी" कह रहे हैं, जहाँ एक शक्तिशाली देश अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों के संप्रभु अधिकारों की अनदेखी करने का फैसला करता है। डेनमार्क से जबरन ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने, कनाडा और अब गाजा को "हथियाने" के उनके विचार, सभी इस धारणा पर आधारित हैं कि अमेरिका अन्य, स्वतंत्र देशों के साथ जो चाहे कर सकता है।
- साथ ही, उन्होंने बार-बार कहा है कि मिस्र और जॉर्डन फिलिस्तीन से शरणार्थियों को लेंगे, जबकि दोनों देशों ने बार-बार कहा है कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि फिलिस्तीनी अपनी ही भूमि पर हैं।
- हालांकि, अन्य लोगों को लगता है कि यह राष्ट्रपति ट्रंप की एक 'बातचीत की रणनीति' है, जहाँ आप एक बेतुकी स्थिति के साथ शुरुआत करते हैं और वहाँ से सौदेबाजी करते हैं। अटलांटिक काउंसिल में वरिष्ठ निदेशक विल वेचस्लेर के अनुसार, "राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सामान्य रणनीति पर चल रहे हैं: आने वाले समय में वार्ता की प्रत्याशा में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लक्ष्य-बिंदुओं को बदलना। इस मामले में यह फिलिस्तीनी प्राधिकरण के भविष्य के बारे में वार्ता है"।

फिलिस्तीनियों के लिए इसके क्या मायने है?

- फिलिस्तीनी पहचान में एक अनुभव जुड़ा हुआ है जिसे 'नकबा' या तबाही कहा जाता है, वे 1948 में इजरायल के निर्माण के बाद अपने जबरन विस्थापन को संदर्भित करते हैं। उस समय, यह यूनाइटेड किंगडम था जिसने उनके भाग्य का फैसला किया था।
- उल्लेखनीय है कि 1917 में ब्रिटेन द्वारा ओटोमन साम्राज्य के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदी मातृभूमि (यहूदियों के पास उस भूमि पर प्राचीन, बाइबल के दावे थे) का वादा किया गया था। क्योंकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों का समर्थन चाहता था, और इसे पाने के लिए, विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने यहूदी नेता बैरन लियोनेल वाल्टर रोथ्सचाइल्ड को लिखे एक पत्र में, इजरायल के लिए समर्थन का वचन दिया।
- जब प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद, फिलिस्तीन ब्रिटिश शासनादेश के अधीन आ गया, और जब ब्रिटेन 1947 में पीछे हटा, तो उसके द्वारा फिलिस्तीनी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, और इजरायल का निर्माण हुआ।

राष्ट्रपति ट्रंप के इस प्रस्ताव पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या रही?

- जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि "मैंने जिन लोगों से भी बात की है, वे सभी इस विचार से खुश हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उस भूमि का एक टुकड़ा हो"। लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी।
- अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने एक बयान में कहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की चाहत में उसका रुख "दृढ़, और अटल" है। साथ ही सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों के उल्लंघन को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, चाहे वह इजरायली बस्तियों की नीतियों के द्वारा हो, चाहे फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने या फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित करने के प्रयासों के माध्यम से हो।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भी इजराइल फिलिस्तीन दो-राज्य समाधान का समर्थन किया।
- चीन ने कहा कि चीन ने हमेशा माना है कि गाजा में युद्ध के बाद के शासन का मूल सिद्धांत फिलिस्तीनी शासन है।

- हमास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प का प्रस्ताव "क्षेत्र में अराजकता और तनाव पैदा करने का नुस्खा" है।
- हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऐसा कुछ है जो "इतिहास बदल सकता है"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अमेरिकी सैन्य विमान से 104 निर्वासित भारतीय वापस लाए गए:

चर्चा में क्यों हैं?

- पंजाब के अमृतसर में 5 फरवरी की दोपहर को अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान 104 निर्वासित भारतीयों को लेकर उतरा। इससे उन लोगों के 'अमेरिकी सपना' धराशायी हो गया, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
- इन निर्वासित लोगों की सबसे अधिक संख्या - 33-33 - गुजरात और हरियाणा से है, उसके बाद पंजाब से 30 लोग हैं। तीन-तीन यात्री महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि दो चंडीगढ़ से हैं। निर्वासित लोगों में 25 महिलाएं और 12 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का यात्री सिर्फ चार साल का है। अड़तालीस व्यक्ति 25 वर्ष से कम उम्र के हैं।

भारतीयों के निर्वासन के पीछे का कारण:

- यह निर्वासन अमेरिका में बढ़ते आव्रजन प्रवर्तन उपायों के बीच हुआ है, जो मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जो देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं या अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहते हैं।
- यह अमेरिका में अनुमानित 11 मिलियन अवैध अप्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यवाही के अनुरूप है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- केंद्र सरकार ने अमेरिका से और अधिक निर्वासन उड़ानों की संभावना से इनकार नहीं किया, कहा कि सभी प्रत्यावर्तित नागरिक जिनके पिछले रिकॉर्ड सत्यापित किए गए हैं, उन्हें "वापस स्वीकार किया जाएगा"।

अमेरिका में कितने 'अवैध' भारतीय हैं?

- अमेरिका में करीब 725,000 अवैध भारतीय नागरिक हैं। ब्लूमबर्ग की एक पिछली रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका करीब 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने की योजना बना रहा है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले अपने नागरिकों को वापस लेकर अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है। क्योंकि भारत के लिए प्राथमिकता यह है कि ये अवैध अप्रवासी, भारतीयों के अमेरिका की वैध यात्रा करने के चैनल में बाधा न डालें।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले कहा था कि भारत अपने नागरिकों, जो अमेरिका सहित अन्य देशों में अवैध रूप से रह रहे हैं, की "वैध वापसी" के लिए खुला है।

भारतीयों के अनधिकृत अमेरिकी प्रवास का क्या कारण है?

- वाशिंगटन डीसी स्थित माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2022 की रिपोर्ट में भारतीयों के अनधिकृत आगमन में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से "भारत में गैर-हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न" और "घरेलू आर्थिक अवसरों की कमी" को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- लेकिन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर देवेश कपूर ने कहा, "अगर यह उत्पीड़न होता, तो हम उम्मीद करते कि मुस्लिम, एससी, एसटी और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोग होते। इसके बजाय, अप्रवासी ज्यादातर पंजाब-हरियाणा और गुजरात से हैं, जहां उनका मानना है कि एक बार वे अंदर आ गए, तो उनके नेटवर्क (प्रवासी समुदाय में) उन्हें बसने में मदद करेंगे।" ये प्रवासी "ज्यादातर युवा" हैं और बेहतर जीवन के लिए "जोखिम उठाने के लिए तैयार" हैं। वे काफी संपन्न परिवारों से होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होते हैं।

ट्रैवल एजेंटों ने गुमराह किया:

- पंजाब सरकार के अधिकारियों को बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित होकर अमृतसर पहुंचे कई पुरुषों और महिलाओं ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें गुमराह किया था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- एक गुजराती परिवार ने दावा किया है कि उसने अमेरिका पहुंचने के लिए 1 करोड़ रुपए चुकाए हैं। अमृतसर के एक गांव के एक युवक के चाचा ने बताया कि परिवार ने अपने भतीजे को विदेश भेजने के लिए डेढ़ एकड़ जमीन बेची और 42 लाख रुपए से कुछ ज्यादा खर्च किए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति के दूसरे विकास इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र:

विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति यात्रा:

- वित्त मंत्री में 2025-26 के अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था के विकास यात्रा के गंतव्य के रूप में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को स्वीकारा है।
- साथ ही वित्त मंत्री द्वारा 'विकसित भारत' को स्पष्ट करते हुए बताया की इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं: गरीबी से मुक्ति; शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा; बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच; शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार; आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं; और देश को 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनाने वाले किसान।
- वित्त मंत्री के अनुसार भारत की विकास की इस यात्रा के लिए: हमारे चार शक्तिशाली इंजन है: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात; ईंधन हैं: हमारे सुधार; हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है: समावेशिता; और लक्ष्य है: विकसित भारत।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- ऐसे में वित्त मंत्री द्वारा भारत की विकास की इस यात्रा के लिए दूसरे शक्तिशाली इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर अपने बजट में महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है।

MSME के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन:

- वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36 प्रतिशत का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये MSME अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं।
- MSME को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी MSME के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुणा तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा।

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

MSME के लिए गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में वृद्धि:

- MSME को ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत:
  - ➢ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा;
  - ➢ स्टार्टअप्स के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत तक कम किया जाएगा; और
  - ➢ अच्छी तरह से संचालित निर्यातक MSME के लिए, 20 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण के लिए।

स्टार्टअप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स':

- स्टार्टअप के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) को 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुए हैं।
- इन्हें 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान से स्थापित 'फंड ऑफ फंड्स' द्वारा समर्थित किया जाता है। अब, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के नए योगदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।

पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना:

- पहली बार उद्यम करने वाले 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से सीख ली जाएगी। उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण का भी आयोजन किया जाएगा।

फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए 'फोकस उत्पाद योजना':

- भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, एक फोकस उत्पाद योजना लागू की जाएगी।
- यह योजना चमड़े के फुटवियर और उत्पादों के समर्थन के अलावा गैर-चमड़े की गुणवत्ता वाले फुटवियर के उत्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनरी का समर्थन करेगी।
- इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय:

- खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर, भारत सरकार भारत को 'खिलौनों के लिए वैश्विक केंद्र' बनाने के लिए एक योजना लागू करेगी।
- यह योजना क्लस्टर, कौशल और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी जो उच्च गुणवत्ता वाले, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाएगी जो 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान' की स्थापना:

- पिछले वर्ष के बजट में घोषित 'पूर्वोदय' योजना के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत सरकार बिहार में 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान' की स्थापना करेगी।
- यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा। इससे:
  - ➢ किसानों की उपज में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी, और
  - ➢ युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन':

- बजट 2025-26 में वित्तमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन' की स्थापना की घोषणा की है। भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीति समर्थन, कार्यान्वयन रोडमैप, शासन और निगरानी ढांचा प्रदान करेगी।
- **इस मिशन में 5 फोकस क्षेत्र शामिल होंगे:**
  - ➢ व्यवसाय करने की सुगमता और लागत;
  - ➢ मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल;
  - ➢ जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र;
  - ➢ प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और
  - ➢ गुणवत्ता युक्त उत्पाद
- **'स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण' पर बल:** 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन' स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना और सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों और कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का इकोसिस्टम तैयार करना होगा।